University in News on 02 February 2021

VISHWAVARTA PAGE 1 & 3

एलयू देश के टॉप विवि से अब प्रतिस्पर्धा करने को तैयार

नेशनल लेवल की रैंकिंग के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कराया पंजीकरण

» पांच चरणों में लविवि ने एनआईआरएफ को भेजा विवरण

विश्ववार्ता संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ यूनिवर्सिटी पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंक की दौड़ में शामिल हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छह साल पहले शुरु हुई इस रैंकिंग के लिए विश्वविद्यालय ने दावेदारी पेश करने में पहली बार हिम्मत जुटाई है।

ऐसे में देश के टॉप यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, इंजिनियरिंग, लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेज और अन्य से लखनऊ विश्वविद्यालय का सीधा मुकाबला है। राजधानी से इससे पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी, केजीएमयू, एकेटीयू और बाबा साहेब भीवराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दौड़ में रहे हैं, पर एलयू पहली बार इस रेस में आया है। लविवि के जिम्मेदारों के मुताबिक नौ में से पांच श्रेणियों में अप्लाई किया है। एमएचआरडी को भेजे गए प्रपोजल में विश्वविद्यालय के 2020-21 सत्र में छात्रों के परिणाम, यहां के पब्लिकेशन, अवार्ड हुई डिग्रियां, पेटेंट फाइल, प्रोजेक्ट्स, शोध, फेकेल्टी की संख्या, फेकेल्टी की योग्यता आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

अब मंत्रालय में गठित टीम प्रपोजल की जांच करेगी और कमियां होने पर संशोधन के लिए भेजेगी। उम्मीद जताई कि लखनऊ विवि को एनआईआरएफ में अच्छी रैंक मिलेगी।

छः साल पहले एनआईआरएफ रैंकिंग का हुआ था आगाज

एनआईआरएफ 29 सितंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। देश में पहली बार चार अप्रैल 2016 को एमएचआरडी ने रैंक सूची जारी की थी। इसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अलावा इंजीनियरिंग, फॉर्मेसी एवं प्रबंधन संस्थान और वास्तुकला संस्थानों जैसे ऑपरेशन के अपने क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न तरह के संस्थानों के लिए अलग रैंकिंग रखी है।

रैंकिंग के आधार पर केन्द्र देता है फंड

देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनआईआरएफ का गठन किया गया है। एमएचआरडी हर साल इसे जारी करता है। केन्द्र सरकार नैक रैंकिंग और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर ही संस्थानों को फंड मुहैया कराती है। वहीं, फ्रेमवर्क संसाधनों, अनुसंधान और हितधारक की धारणा जैसे रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कई मापदंडों को देखा जाता है। इन्हें पांच समूहों में बांटा गया है।

पब्लिक ओपिनियन है अहम आधार

एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए यह भी मायने रखता है कि संस्थान के बारे में पब्लिक की क्या राय है। जनता की राय के 25 नंबर जुड़ते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय यह प्रपोजल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है। वहीं, मंत्रालय अखबारों के जरिये विज्ञापन जारी करता है और जनता की राय मांगता है। फिर संबंधित संस्थान के बारे में जो राय मिलती है, उसके भी नंबर रैंकिंग में जुड़ते हैं। जानकारी के मुताबिक इस महीने के आखिरी में एनआईआरएफ की रैंकिंग जारी होगी।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ मजबूत कदम

प्रो. मनोज अग्रवाल

कोरोना काल के उत्तरार्द्ध में प्रस्तुत मोदी सरकार का यह बजट जन-अपेक्षाओं पर बेहतर साबित होना चाहिए। वित्तमंत्री ने इस बजट के माध्यम से विशेष आर्थिक रणनीति को प्रदर्शित किया है। राजस्व की वसूली में कमी के बाजवूद सरकार ने खर्चों में बढ़ोत्तरी जारी रखी है, ताकि अर्थव्यवस्था में सिकुड़न की स्थिति न पैदा हो। और अर्थ व्यवस्था में मांग में तेजी हो और विकास दर में तेजी लाई जा सकें।

छह महत्वपूर्ण स्तम्भों पर आधारित इस बजट की रणनीति दीर्घकालीन विकास के लिए सहायक होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के कारण यह न केवल देश के नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करेगा, बल्कि विश्व के लगभग 100 देशो को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतारने की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। बजट में कई वर्षो के बाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विशेष रणनीति दिखाई पड़ती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुनियादी सुविधाओं के विकास को वित्त मंत्री ने नई गति प्रदान की है। इसके तहत राजमार्गों का तेजी से विकास और चार राज्यों पर विशेष ध्यान देना शामिल है। मेट्रो रेल परियोजनाओं को पूरे देश में तेजी से साकार करने के लक्ष्य के साथ भारतीय रेलों का स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीरण के लिए व्यापक धन उपलब्ध कराया गया है। विद्युत क्षेत्र के विकास-सुधार तथा सौर उर्जा पर पर और अधिक जोर दिया गया है। मानव विकास के लिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार व विकास इस बजट की प्राथमिकताओं में एक है। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए उच्च शिक्षा आयोग के गठन से छात्रों एवं शोधार्थियों को लाभ होगा। शोध के बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षो में 50 हजार करोड़ रुपए धन का आवंटन किया गया है। 15 हजार नए मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय किया गया है। जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल शामिल है। इसके साथ ही 100 नए सैनिक विद्यालय भी खोले जाने हैं। यह शिक्षा क्षेत्र में विशेष क्षेत्र मे विशेष पहल है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी व्यापक रूप से मिलेगा।

बजट

कुल मिलाकर यह बजट आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कोरोना से उत्पन्न संकट से उभरने में मदद मिलेगी ही। साथ ही रोजगार, आय-वृद्धि और अर्थव्यवस्था को नया आयाम प्राप्त हो सकेगा। मोदी सरकार के अब तक के बजट में यह बजट सर्वोत्तम प्रभावशाली बजट कहा जा सकता है।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री हैं)

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

लविवि ने एआईआरएफ के लिए किया आवेदन

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। स्थापना के 100 साल पूरे कर चुका लखनऊ विश्वविद्यालय देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल हो गया है। विवि ने इस साल होने वाली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के लिए आवेदन कर दिया है।

हालांकि अभी भी नैक के आवेदन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई है। लविवि की नैक की ग्रेडिंग एक साल पहले समाप्त हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस सत्र की समाप्ति से पहले विवि नैक के लिए भी आवेदन कर देगा। एमएचआरडी ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्ष 2015 में एनआईआरएफ का गठन किया गया है।

नैक के लिए अभी इंतजार

केंद्र सरकार नैक रैंकिंग और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर ही संस्थानों को अनुदान देता है। अप्रैल 2016 को एमएचआरडी ने रैंक सूची जारी की थी। इसमें विश्वविद्यालय, कॉलेजों के अलावा इंजीनियरिंग, फॉर्मेसी व प्रबंधन संस्थान, वास्तुकला और चिकित्सा शिक्षा संस्थान शामिल होते हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक लविवि इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहा था। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने ज्वॉइनिंग के समय ही इस रैंकिंग में शामिल होने की बात कही थी। अब लविवि ने आवेदन कर दिया है।

राजधानी के कई संस्थान करते हैं आवेदन

राजधानी में इससे पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल ला यूनिवर्सिटी, केजीएमयू, एकेटीयू और बीबीएयू एआईआरएफ के लिए आवेदन करते आ रहे हैं।

विवि के साथ ही विधि, इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में दावेदारी

एआईआरएफ की रैंक के लिए विवि की कैटेगरी में आवेदन करने के समय विधि और इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित सूचनाएं ली जाती हैं। ऐसे में लविवि की विधि और इंजीनियरिंग की सूचनाएं भी देनी पड़ी है। रैंकिंग जारी करते समय विधि और इंजीनियरिंग की अलग रैंक भी जारी होगी।

संवाद में वीसी को बताईं समस्याएं

माई सिटी रिपोर्टर

छात्रों से संवाद करते लविवि वीसी।

लखनऊ। दो तल का छात्रावास है, इसके बावजूद गीजर और वाशिंग मशीन की सुविधा सिर्फ एक ही तल पर मिल रही है। कपड़े धोने और नहाने के लिए दूसरे तल पर जाना पड़ता है।

लविवि में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के साथ शुरू हुई संवाद प्रक्रिया के तहत पहले ही दिन सुभाष छात्रावास के विद्यार्थियों ने अपना दर्द बयां किया। कुलपति ने चीफ प्रवोस्ट को तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। वर्तमान समय में सुभाष छात्रावास में मरम्मत का कार्य होने के कारण इन छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में स्थानांतरित किया गया है। संवाद के दौरान छात्रों ने कुलपति को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बताया कि लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में भूतल एवं प्रथम तल पर समाचार पत्र आता है, जबकि वे लोग द्वितीय तल पर रहते हैं। वे समाचार पत्र अपने साथ ले नहीं जा सकते। संवाद में डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. पूनम टंडन, चीफ प्रवोस्ट प्रो. नलिनी पांडेय व सुभाष छात्रावास के प्रवोस्ट डॉ. एन के सिंह मौजूद थे।

अब 15 तक भरे परीक्षा फॉर्म

लखनऊ। लविवि ने प्रथम वर्ष के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। यह अंतिम मौका होगा। लविवि की सेमेस्टर परीक्षा 28 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसमें प्रथम वर्ष की क्लास शामिल नहीं हैं। इसलिए उनको परीक्षा फॉर्म भरने का एक मौका और दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. आनंद मुरारी सक्सेना ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थियों का उसका प्रिंट आउट भी जमा करना है। फॉर्म लविवि परिसर के विद्यार्थियों को भी भरना है, लेकिन उन्हें इसकी फीस नहीं जमा करनी है।

प्रो. सोमेश देवरस शोधपीठ की जिम्मेदारी

लखनऊ। लविवि के वाणिज्य संकाय में स्थापित भाऊराव देवरस शोधपीठ के निदेशक की जिम्मेदारी प्रो. सोमेश शुक्ला संभालेंगे। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के निर्देश पर कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने इसका सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया।

HINDUSTAN PAGE 9

भारत के विकास के आधार स्तंभ के तौर पर इस बजट को देखा जाना चाहिए

प्रोफेसर एमके अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विवि

लखनऊ। बजट की विशेषता यह है कि कोरोना के अंतिम चरण में प्रस्तुत पहला बजट विस्तारवादी विचार की रणनीति उजागर करता है। वित्त मंत्री की आर्थिक रणनीति स्पष्ट है। पहली तो यह कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त किया जाए। जिसके लिए छह आधार स्तंभ का सहारा लिया है। ये हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण, औद्योगिक विकास, कृषि सुधार एवं कृषि विकास, मानव पूंजी को सशक्त एवं संबल प्रदान करना, शोध एवं विकास तथा सुशासन। स्वास्थ्य एवं कल्याण पर वित्त मंत्री ने सर्वाधिक वृद्धि की है। यह विगत बजट से डेढ़ गुना अधिक है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए विशेष बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का धन इनमें शामिल है। बुनियादी सुविधाओं के विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास किया है। प्रवासी श्रमिकों के हित को भी ध्यान में रखा है। कह सकते हैं कि इस बजट को नए भारत के विकास के आधार स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए।

एलयू: परीक्षा शुल्क 15 तक जमा होगा

लखनऊ। एलयू प्रशासन ने स्नातक सेमेस्टर कक्षाओं के बीए, बीएससी, बीकॉम, प्रबंधकीय, यूजी तथा पीजी, पीजी डिप्लोमा, विधि, बीकॉम ऑनर्स आदि तथा एग्जमटेड कोर्सों के परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है।

DAINIK JAGRAN PAGE 9

अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बजट

कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने अपनी आर्थिक प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इसका सूत्रपात 12 मई 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसने कोरोना संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद की। इसी से प्रेरित होकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को प्रस्तुत किया, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी आयामों को प्रबल प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इस बार बजट के आकार को कम करने के बजाए वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 16 फीसद अधिक व्यय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह वृद्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्व संग्रह में कमी आई है। यही नहीं, पूंजीगत व्यय में 35 फीसद की वृद्धि की गई है ताकि अर्थव्यवस्था के तेज प्रगति के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके।

प्रो. एमके अग्रवाल, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

बजट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर भी काफी फोकस है। नए स्कूल खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा में आयोग गठित होगा, इससे सभी संस्थानों की मानीटरिंग एक जगह से हो सकेगी। प्राइवेट सेक्टर के विवि एवं कालेजों के शिक्षक भी रिसर्च ग्रांट के लिए अर्ह होंगे। ओवरआल बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है।

संजय मेधावी, विभागाध्यक्ष, एमबीए, लविवि

RASHTRIYA SAHARA PAGE 2 & 5

हास्टल में रह रहे छात्रों ने कुलपति को बतायीं समस्याएं

लखनऊ (एसएनबी)। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय ने सुभाष छात्रावास के छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया। वर्तमान समय मे सुभाष छात्रावास में मरम्मत का कार्य होने के कारण इन छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में स्थानांतरित किया गया है।

संवाद के दौरान छात्रों ने कुलपति को वताया कि लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में भूतल एव प्रथम तल पर समाचार पत्र आता है, जवकि वे लोग द्वितीय तल पर स्थानांतरित किये गए है, जहां समाचार पत्र नही आता। इसी प्रकार द्वितीय तल पर वाशिंग मशीन और गीजर की भी सुविधा नही है। कुलपति ने चीफ प्रोवोस्ट को तत्काल इन व्यवस्थाओं को लागू करने के निर्देश दिए।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ मजबूत कदम

कोरोना काल के उत्तरार्द्ध में प्रस्तुत मोदी सरकार का यह वजट जनअपेक्षाओं पर वेहतर सावित होना चाहिए। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वजट के माध्यम से विशेष आर्थिक रणनीति को प्रदर्शित किया है। राजस्व वसूली में कमी के वावजूद सरकार ने खर्चे में वढ़ोतरी जारी रखी है ताकि अर्थव्यवस्था में सिकुड़न की स्थिति न पैदा हो, मांग में तेजी हो तथा विकास दर में तेजी लायी जा सके।

त्वरित टिप्पणी

प्रो. एमके अग्रवाल
लखनऊ विश्वविद्यालय

छह महत्वपूर्ण स्तम्भों पर आधारित यह वजट दीर्घकालीन विकास के लिए सहायक होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के कारण यह न केवल देश के नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करेगा, वल्कि विश्व के लगभग 100 देशों को कोविड वैक्सीन उपलव्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतारने की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम वढ़ाएगा। कई वर्षों वाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विशेष रणनीति दिखायी पड़ती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वुनियादी सुविधाओं के विकास में वित्तमंत्री ने नयी गति प्रदान की है। इसके अन्तर्गत राजमार्गों का तेजी से विकास तथा चार राज्यों पर विशेष ध्यान देना शामिल है। मेट्रो रेल परियोजनाओं का पूरे राष्ट्र में तेजी से विकास करना तथा भारतीय रेलवे को स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण हेतु व्यापक धन उपलव्ध कराया गया है। विद्युत क्षेत्र के विकास, सुधार तथा स्वच्छ ऊर्जा पर और अधिक जोर दिया गया है।

मानव विकास हेतु शिक्षा क्षेत्र में सुधार व विकास इस वजट की प्राथमिकताओं में एक है। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार हेतु उच्च शिक्षा आयोग के गठन से छात्रों व शोधार्थियों को लाभ होगा। शोध को वढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 15 हजार नये माडल स्कूल खोलने का निर्णय किया गया है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 750 एकलव्य माडल स्कूल सम्मिलित हैं। इसके साथ ही 100 नये सैनिक विद्यालय भी खोले जाने हैं। यह शिक्षा क्षेत्र में विशेष पहल है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी व्यापक रूप से मिलेगा।

कुल मिलाकर यह वजट आत्मनिर्भरता की ओर वढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कोरोना से उत्पन्न संकट से उवरने में मदद मिलेगी ही, साथ ही रोजगार आय-वृद्धि व अर्थव्यवस्था को नया आयाम प्राप्त हो सकेगा। मोदी सरकार के अव तक के वजट में यह सर्वोत्तम प्रभावशाली वजट कहा जा सकता है।

THE PIONEER PAGE 3

Over 1,000 applications received for university's Karmayogi Scholarship

PNS ■ LUCKNOW

The recently launched 'Karmayogi Scholarship' by Lucknow University has received a good response, according to DSW Poonam Tandon. She said they have received over 1,000 applications for the scholarship in which students are allowed to earn even as they learn.

She said it's a good figure because nearly 50 per cent of the students are already getting some kind of scholarship and there are several bars as regards who could avail of the scholarship. There are some criteria which have to be met by the students. "The students should not be receiving scholarships from elsewhere, their family income should not be more than Rs 3 lakh, they should have obtained 60 per cent marks in the previous exams and there should be no disciplinary action against them," she said. She further pointed out that they have asked for vacancies from all offices and departments of LU.

"The Psychology department has the 'Happy Thinking Lab' and two students are required for its maintenance. The research cell also needs two students. Also, for the BEd examinations this year, we are mulling a call centre which will also be handled by students who get the scholarship," she said.

"The students will be allowed to work for two hours only for 50 days. They will be given Rs 300 for two hours of work. The students won't be working during class hours as we don't want their studies to be hampered," she added.

i-NEXT PAGE 1 & 3

एलयू प्रोफेसर भर्ती में दिव्यांगों का भी कोटा

रोस्टर के नियम में फिजिकली हैंडीकैप कैंडीडेट्स को नहीं दिया गया लाभ

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दर्ज कराई आपत्ति, एलयू करेगा सुधार

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (1 Feb): लखनऊ यूनिवर्सिटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी अधिसूचना में कॉरिजेन्डम (शुद्धिपत्र) जारी करेगा. एलयू भर्ती प्रक्रिया में रिजर्वेशन कोटे में बदलाव की तैयारी कर रहा है. सूत्रों की मानें तो भर्ती प्रक्रिया में फिजिकली हैंडीकैप कोटे का निर्धारण नहीं किया है. इसको लेकर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थीं.

कमेटी आज देगी अपनी रिपोर्ट

एलयू सूत्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी रोस्टर के नियम को लागू कर सीटें निर्धारित की गई हैं. रोस्टर में दिव्यांगजनों के लिए कोटा नहीं निर्धारित किया गया है जबकि शासन की ओर से जारी आदेशों में इसका लाभ दिया जाना है. सूत्र बताते हैं कि मामले की जानकारी होने के बाद दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने एलयू से संपर्क किया और इसमें सुधार कर इसका लाभ कैंडीडेट्स को देने के लिए कहा है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने को कहा है. रिपोर्ट मिलने के बाद यूनिवर्सिटी इसे अनुमोदन के लिए दोबारा से राज्य सरकार को भेजेगी. फिर इसमें सुधार करेगी.

180 पदों के लिए भर्ती

एलयू ने सितंबर में 180 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके लिए 5084 आवेदन प्राप्त हुए हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन पदों को भरने के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के बिना आवेदन आमंत्रित किये थे. वहीं एलयू के सूत्रों का कहना है कि अनजाने में गलती हुई है क्योंकि नियुक्तियों के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों में इस तरह के कोटा का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था. इसी को देखते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के आयुक्त कार्यालय ने यूनिवर्सिटी को भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के आरक्षण का प्रावधान करने को कहा है.

करीब छह पदों का फंसेगा पेंच

लखनऊ यूनिवर्सिटी के सूत्रों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को मिलने वाला कोटा लागू किया जाएगा तो इस हिसाब से कुल सीटों के सापेक्ष छह सीटें बनेंगी. इसमें तीन सीटें सहायक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर की सीट बनेगी. वही यह सीटें किन विभागों में होगी, इसका निर्णय कमेटी करेगी. सूत्रों का कहना है कि मामले को सुलझाने के बाद कुछ विभागों की सीटों के आरक्षण के नियम को बदला जाएगा.

180 पदों पर होनी है भर्ती

05 हजार आवेदन आए हैं

आत्मनिर्भरता की ओर सार्थक कदम

VoL PAGE 1

रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे, पर मध्यम वर्ग को झटका

बजट से सामान्य चीजों के दाम बढ़ेंगे

दीर्घकालीन विकास में सहायक होगा बजट